(c) What is the amount involved in purchasing these vehicles;

(d) whether the dealers of these vehicles received Rupees 3,000 as handling charges for each vehicle; and

(e) if so, how much amount was received by these dealers in various States, including Pondicherry and whether they are entitled to the said amount?

THE MINISTER OF COMMERCE AND FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI P. SHIV SHANKER): (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) and (e) There is no provision in DGS&D Rate Contracts or ad-hoc contracts for payment of Rs. 3,000 as handling charges for each vehicle. These contracts provide for payment of the net dealer's price of the vehicle to the manufacturer exclusive of dealer's commission. In respect of contracts placed against requirements of Civil Departments there is a provision for payment of a mark-up ranging from Rs. 1000-each for Ambassador Cars, Premier Cars Mahindra & Mahindra jeeps and allied and commercial vehicles to Rs. 2000-each for Tata Trucks. This amount is also paid to the manufacturers alongwith the net dealer's price of the vehicle. This mark-up is meant to be paid by the manufacturers to their dealers, through whom the vehicles are delivered to the consignee to cover the expenses of pre-delivery inspection and other free services. The Department is not aware of the amount paid by the manufacturers to their agents (dealers) for supplies made against the DGS&D Contracts.

Violation of labour laws by MES contractors

1097. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Maintenance Engineering Service contractors who are executing the contracts at Rajpur have flouted the labour laws by paying salaries below the minimum wages and by not extending labour welfare measures;

(b) whether this Ministry has taken any steps to ensure the implementation of labour laws strictly in the construction industry at Rajpur; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) and (b) MES (Military Engineeringr Service) works at Raipur have commenced from May, 1985. There are 23 MES Contractors' establishments in the area. Regular inspections are conducted from time to time by the Officers of the Central Industrial Relations Machinery. Forty inspections have been conducted under various laws namely Conctracts Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970. Minimum Wages Act, 1948; Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 and equal Remuneration Act.

(c) 8 prosecutions have been launched and one claim case is being filed under Minimum Wages Act.

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कपड़ा मिलों द्वारा कपड़े का जलाया जाना

1098. श्री अश्विनी कुमार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जनवरी, 1986 के कानपुर से प्रकाशित दैनिक "विश्वमित्र" में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अर्थटन कपडा मिल के अधिकारियों द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपये की कीमत का 25 हजार मीटर कपड़ा जलाया गया है जिसमें से कुछ वहां के सतर्कता विभाग द्वारा पकडा भी गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उस मिल के श्रमिक संघ ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है और यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान): (क) जी हां ।

(ख) महायक निगम द्वारा की गई जांच के आधार पर पाया गया है कि लगभग 3200 रु. मूल्य का लगभग 1,000 मीटर कपडा केमिकल प्रासैसिंग में टैंडरिंग की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया । यह कहना गलत है कि 1.5 लाख रु. मूल्य का 25 हजार मीटर कपड़ा जला दिया गया है ।

(ग) एन.टी.सी. प्रबन्ध-मण्डल ने इस लापरवाही के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने और इस संबंध में उचित कार्यवाही किये जाने के बारे में जांच के आदेश दिये हैं । ट्रेड यूनियनों ने भी जांच की मांग की किन्तु जांच पहले ही आरम्भ कर दी गई है ।

Bank fraud in Bombay

1099. SHRI RAM NARESH KUSHAWAHA:
SHRI VIRENDRA VERMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a big bank fraud involving Rs. 35 crores has been recently unearthed in Bombay; and

(b) if so, what are the details thereof stating the status of the bank officials involved in the racket, their *modus operandi* and the action taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) Presumably the reference is to the allegations about collusion of some officials of commercial banks and the National Co-operative Bank Ltd. Bombay in opening of Letters of Credit and transfer of foreign exchange out of the country without actual import of goods in an irregula manner. The Reserve Bank of India has reported that about 200 Letters of Credit were opened with various commercial banks through the National Cooperative Bank Ltd. Bombay. According to Reserve Bank of India the Anti-Corruption Bureau Maharashtra is investigating into the matter and the involvement of the bank officials and the *modus operandi* adopted etc. would be known only after the investigation is completed.

मध्य प्रदेश में शुष्क पत्तन तथा विमान-माल काम्पलैक्स का स्थापित किया जाना

1100. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **क्या मध्य प्रदेश में शुष्क पत्तन तथा विमान-माल** काम्पलैक्स की स्थापना की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री तथा खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : मध्य प्रदेश में शुष्क पत्तन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । एयर कार्गो काम्पलैक्सों की स्थापना पर, संबंधित राज्य सरकारों की, जो उनका प्रबन्ध करती है, सिफारिश की संभाव्यता के अनुसार विचार किया जाता है । इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से अभी तक ऐसा कोई ब्यौरेवार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसके समर्थन में यातायात संबंधी औचित्य दिया गया हो ।

समाज के कमजोर वर्गों को ऋण दिया जाना

1101. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने समाज के कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों के व्यक्तियों को कर्ज दिए जाने संबंधी नियमों को हाल ही में उदार बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पूजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में जमानत और मार्जिन के वास्ते उदार मानदण्ड निर्धारित किये हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने विभेदी ब्याज दर योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों और